Regarding need to deport Bangladeshi infiltrators from Assam-Laid

श्री दिलीप शइकीया **(दारंग-उदालगुड़ी) :** असम में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मुद्दा राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और यह असम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे यहाँ की जनसांख्यिकी में भी भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है । 1951-2011 की अवधि में असम राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 288.21% रही, जबकि पूरे भारत में यह 235.15% थी । यह उच्च वृद्धि दर असम राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवासन का संकेत देती है । इनके यहाँ बसने से राज्य में वन भूमि का प्रतिशत 1951-52 के 39% से घटकर अब लगभग केवल 30% रह गया है । असम समेत पूर्वोत्तर भारत में अवैध घुसपैठ को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई समझौता नहीं होने के कारण, बांग्लादेश द्वारा अपने इन अवैध घुसपैठियों को वापिस नहीं लिया जाता है । अधिकांश बांग्लादेशी प्रवासियों ने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है वोट बैंक की प्रतिस्पर्धी राजनीति और पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा इन घुसपैठियों को दिया गया संरक्षण आज इस क्षेत्र के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो रहा है । मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बांग्लादेश के साथ इस अवैध घुसपैठ को लेकर एक समझौता किया जाए और अवैध घुसपैठियों को वापिस भेजा जाए ।